भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1723 का उत्तर

नई एक्सप्रेस/सुपरफास्ट और वंदे भारत ट्रेन चलाना

1723. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा क्षेत्र रेल सुविधाओं के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण यात्रियों, पर्यटकों और सैनिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिले और अन्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पटरियां बिछाने, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, स्टेशन के आधुनिकीकरण या नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जैसलमेर से जोधपुर, बाड़मेर-जोधपुर से जयपुर, दिल्ली या दक्षिण भारत के लिए लंबी दूरी की अतिरिक्त रेलगाड़ियों की पुरानी लंबित मांग को देखते हुए नई एक्सप्रेस/सुपरफास्ट या वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजनाओं और कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित, स्वीकृत बजट में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल नेटवर्क राज्यों/जिलों की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है, तदनुसार, नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार, रेलगाड़ियों को राज्यों की सीमाओं के आर-पार शुरू किया जाता है। वर्ष 2021-2022 से 2025-2026 (दिनांक 25.07.2025 तक) के दौरान, भारतीय रेल ने बाड़मेर के लिए 04 गाड़ी सेवाएँ और जैसलमेर स्टेशन के लिए 02 गाड़ी सेवाएँ शुरू की हैं।

तदनुसार, वर्तमान में, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर स्टेशनों पर क्रमशः 28, 24 और 14 गाड़ी सेवाएँ परिचालित की जा रही हैं, जो बाड़मेर और जैसलमेर को जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, जम्मू तवी, अंबाला, काठगोदाम, ऋषिकेश, जालंधर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, यशवंतपुर, हावड़ा आदि जैसे विभिन्न गंतव्य स्थानों से जोड़ती हैं।

वर्तमान में, बाड़मेर को जयपुर और दिल्ली से क्रमशः 04 जोड़ी और 03 जोड़ी गाड़ियां से सीधे जोड़ती हैं। इसी प्रकार, जैसलमेर स्टेशन जयपुर और दिल्ली से दो-दो जोड़ी रेल सेवाओं द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल में वंदे भारत गाड़ी सेवाओं सहित नई रेल सेवाओं को शुरू करना सतत् प्रक्रिया है, जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार/जिला-वार, क्योंकि ये रेल परियोजनाएँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों की सीमाओं के आर-पार भी फैली हो सकती हैं।

रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात संबंधी अनुमान, अंतिम छोर तक संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/असंतृप्त लाइनों में बढ़ोतरी, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉर्वर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 43,918 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 3,409 किलोमीटर लंबाई की 28 रेल परियोजनाएँ (13 नई लाइन, 05 आमान परिवर्तन और 10 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,238 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2025 तक 18,955 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इन कार्यों की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	13	981	196	5769
आमान परिवर्तन	5	1252	788	6829
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	10	1176	254	6357
कुल	28	3,409	1,238	18,955

बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली इन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	भैरव गुफा और कैलाश टेकरी के रास्ते रामदेवरा-पोखरण के बीच नई लाइन (13 कि.मी.)	189
2.	लूनी-समदरी-भिलड़ी खंड का दोहरीकरण	3086

उपरोक्त परियोजनाओं का विद्युतीकरण कार्य भी प्रगति पर है।

पिछले तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25 और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों सहित राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 5,497 किलोमीटर लंबाई की कुल 55 परियोजनाओं (23 नई लाइन और 32 दोहरीकरण) का सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत किया गया है।

परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन जैसे आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। चूँकि परियोजना की स्वीकृति सतत और गतिशील प्रक्रिया है, अतः सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, किसी विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में आवश्यकतानुसार कार्य किए जाते हैं, जो पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों को मंजूरी देने और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसमें स्टेशन तक पहुँच मार्ग में सुधार, परिचलन क्षेत्र,

प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफ़ॉर्म की सतह का कार्य और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर, साफ-सफाई, नि:शुल्क वाई-फ़ाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूदृश्यांकन आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन करना शामिल है स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

इस योजना में, स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन को शहर के दोनों ओर एकीकृत करना, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान राज्य के 85 स्टेशनों सहित 1337 रेलवे स्टेशनों को विकास हेतु चिह्नित किया गया है। राजस्थान राज्य में इस योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
राजस्थान	85	आबू रोड, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, असलपुर जोबनेर, बालोतरा, बांदीकुई, बारां, बाड़मेर, बयाना, ब्यावर, भरतपुर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा, बिजयनगर, बीकानेर, बूंदी, चंदेरिया, छबड़ा गुगोर, चित्तौड़गढ़ जं., चूरू, डाकनिया तलाव, दौसा, डीग, देगाना, देशनोक, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, फालना, फतेहनगर, फतेहपुर शेखावटी, गांधीनगर जयपुर, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोटन, गोविंदगढ़, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर जं, जैसलमेर, जालौर, जवाई बांध, झालावाड़ सिटी, झुंझुनू, जोधपुर, कपासन, खैरथल, खेरली, कोटा जं, लालगढ़ जं, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मारवाड़ भीनमाल, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन, मेड़ता रोड जं, नागौर, नरैना, नीम का थाना, नोखा, पाली मारवाड़, फलौदी जं, फुलेरा जं, पिंडवाड़ा, रायसिंह नगर, राजगढ़, रामदेवरा, रामगंजमंडी जं., राणा प्रतापनगर, रानी, रतनगढ़ जं, रेन, रींगस, सादुलपुर, सांगानेर, सवाई माधोपुर, श्री महावीरजी, सीकर, सोजत रोड, सोमेसर, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, उदयपुर सिटी

राजस्थान राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अभी तक, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 08 स्टेशनों (बूंदी, देशनोक, फतेहपुर शेखावटी, गोगामेरी, गोविंदगढ़, मंडलगढ़, मंडावर-महवा रोड और राजगढ़) के चरण-I के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं और कुछ उपयुक्त स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- बाड़मेर स्टेशन पर, स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक, प्लेटफ़ॉर्म की सतह की ऊंचाई बढ़ाने, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर और परिचलन क्षेत्र के संरचना संबंधी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। स्टेशन भवन का फिनिशिंग कार्य, प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 के सुधार कार्य, नए पैदल पार पुल और लिफ्ट का निर्माण आदि कार्य शुरू किए गए हैं।
- जैसलमेर स्टेशन पर, प्रस्थान और आगमन ब्लॉक, एयर कॉन्कोर्स, पैदल पार पुल, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर, प्लेटफ़ॉर्म की सतह का सुधार कार्य, सब-स्टेशन भवन और सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र सहित स्टेशन भवन का कार्य पूरा किया जा चुका है। परिचलन क्षेत्र का विकास, लिफ्ट और एस्केलेटर संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- बालोतरा स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक, प्लेटफार्म की सतह की ऊंचाई बढ़ाने और प्लेटफार्म शेल्टर का संरचना संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। परिचलन क्षेत्र में सुधार, नए पैदल पार पुल और लिफ्टों का निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत वित्तपोषण किया जाता है। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण हेतु निधियों के आवंटन का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार अथवा राज्य-वार। राजस्थान राज्य 5 (पाँच) रेलवे जोनों, अर्थात् उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, के अंतर्गत आता है। इन जोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 5,257 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है और अभी तक (जून, 2025 तक) 1,024 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

*****